Volume-2, No. II, Aug-2015, pp. 87-89

वैश्वीकरण अथवा भूमण्डलीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

श्री हुकम सिंह
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
श्री दलीप सिंह
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सार
भारत की नई आर्थिक नीति का मूलभूत उद्देश्य उदारीकरण की नीति अपनाकर निजीकरण को प्रोत्साहित करना और देश की अर्थव्यवस्था के सार्वभौमीकरण के लिये मार्ग प्रशस्त करना है। इस नीति के अन्तर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था एवं विश्व बाजार से अच्छी तरह जोड़ने तथा उसे अधिक प्रतियोगी बनाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का सार्वभौमीकरण करना आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में अधिक प्रतियोगी बाजारोन्मुख बनाने के लिये देश में उदारीकरण, निजीकरण एवं सार्वभौमीकरण का जो त्रि–सूत्रीय फॉर्मूला अपनाया गया है उससे आशा की जाती है कि देश में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिये उचित वातावरण तैयार होगा और भारतीय व्यापार विश्व के अधिक से अधिक देशों के साथ विस्तृत होगा। सार्वभौमीकरण वस्तुतः विभिन्न देशों के बीच अपेक्षाकृत एवं उदार व्यापारिक सम्बन्ध बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है।

मुख्य शब्दः भूमण्डलीकरण, सार्वभौमिकरण, नई आर्थिक नीति, विकासशील देश, विकसित देश, औद्योगिकरण, आर्थिक विषमता, कृषि व्यापार

सार्वभौमीकरण की नीति में प्रतियोगी संस्कृति के विकास के साथ उच्च दक्षता वाली उत्पादकता को बढ़ावा देना, तकनीकी हस्तान्तरण शोध एवं विकास के कार्यक्रमों में आपसी सहयोग का लाभ उठाना आदि सम्मिलित है ताकि देश को 'बन्द अर्थव्यवस्था' के दोषों से मुक्त करके 'खुली अर्थव्यवस्था' के रूप में बदला जा सके। नई आर्थिक नीति के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर एक समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया। इस नीति में न केवल औद्योगिक क्षेत्र बल्कि समूची अर्थव्यवस्था में विकास की नई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई। नई आर्थिक नीति में वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा देश के लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा आर्थिक विकास के मार्ग पर ले जाया जा सके। सरल शब्दों में, उदारीकरण का अर्थ नियमों एवं प्रतिबन्धों में ढील देने अथवा उदाहरण बरतने से है। जब सरकार उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आयात–निर्यात आदि क्षेत्रों में या तो प्रतिबन्धों को कम कर देती हो या फिर समाप्त कर देती हो तो यह कहा जाता है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कर दिया गया हो। नई आर्थिक नीति में अपनाए गए सुधारवादी उपायों की परिणति आज उदारीकरण एवं निजीकरण की सीमा से निकलकर अर्थव्यवस्था के सार्वभौमीकरण के रूप में परिलक्षित हो रही है। सार्वभौमीकरण शब्द आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गुंजायमान है। यह शब्द व्यापार अवसरों की जीवन्तता एवं उनके विस्तार का द्योतक है। सार्वभौमीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रिया–कलापों विशेषकर विपणन सम्बन्धी क्रियाओं का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करता है जिसमें सम्पूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में ''सार्वभौमीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबन्धित न रहकर विश्व बाजार में निहित तुलनात्मक लागत लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। नई आर्थिक नीति में सार्वभौमीकरण का घटक देशों के मध्य प्रशुल्क एवं अन्य नियंत्रणात्मक अवरोधों को समाप्त करके घरेलू उद्योगों को विदेशी वस्तुओं को कड़ी प्रतिस्पर्द्धा योग्य बनाने का प्रयास है। स्वतंत्रता के बाद चार दशकों की संरक्षणात्मक नीति ने भारतीय उद्योगों को गुणात्मक रूप से कमजोर बनाया गया है।

विकसित देश और वैश्वीकरण–विकसित, पूँजीवादी, पाश्चात्य देशों के लिए भू–मण्डलीकरण एक लाभ जनक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण उदारवादी मान्यताओं पर आधारित होने के कारण विकसित देशों के आर्थिक सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं के अनुकूल होता है। इसके माध्यम से विकसित देश अपने दमित औपनिवेशिक साम्राज्यवादी मनसूबों को पूरा करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था तथा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटने, पूँजी के खुले प्रवाह तथा विकसित तकनीक के कारण सर्वाधिक लाभ विकसित देशों को ही पहुँचता है। विकासशील देशों को

पूँजी निवेश तथा आर्थिक लाभ का झाँसा देकर विकसित देश प्राकृतिक संसाधनों का निर्ममता से दोहन करते जिससे परिस्थितिकीय अंवतुलन जैसी विकराल समस्या पैदा होती है। विकासशील देशों पर कर्ज का उच्च ब्याज की दर पर कार्य लाद कर विकसित देश उनकी राजनीतिक स्वतंत्रा का भी दमन करते है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भू–मण्डलीयकरण विकसित देशों के लिए बहुमुखी लाभ की प्रक्रिया है। विकासशील देश और वैश्वीकरण–विकसित पश्चिमी देशों के साम्राज्यवादी मनसूबों और विश्व व्यापार संगठन के झासों के कारण अधिकतर विकासशील देश उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की ओर मोहित हो जाते हैं। भू–मण्डलीयकरण की प्रक्रिया में इन विकासशील देशों को तत्कालीन लाभ अवश्य पहुँच पाता है जैसे– पूँजीनिवेश के कारण इनके यहाँ औद्योगीकरण की गति तीव्र हो जाती है। अमूल्य प्राकृतिक घरोहरों संसाधनों के अन्धाधुन्ध दोहन से इन्हें कुछ आय मिलने लगती है। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के नाम पर पश्चिमी देशों की पिछड़ चुकी तकनीक इन्हें सस्ते में मिल जाती है जिससे उनके स्वदेशी उत्पादन के लागत कुछ कम हो जाती है परन्तु दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भू–मण्ड़लीयकरण इन देशों के लिए घातक है इन देशों पर कर्ज का बोझ धीरे–धीरे इतना बढ़ जाता है कि उनके बजट का अधिकांश भाग विदेशी ऋण के ब्याज की देनदारी में चला जाता है निर्मम दोहन के कारण इनके प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाते हैं इनकी राजनीतिक स्वतंत्रता व स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता गम्भीर रूप से प्रतिस्पर्द्धा करने के नाम पर ये देश आवश्यक सेवाएं जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य भोजन शुद्ध पेयजल आदि जनता को मुहैया कराने से वंचित हो जाते हैं परिणाम स्वरूप मृत्यु–दर बढ़ती है। जन स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाती है। वैश्वीकरण से इन देशों में जहाँ एक अत्यन्त छोटा वर्ग दिन–दुगनी रात–चौगनी तरक्की करता है। वही दूसरी ओर बहुसंख्यक जनता की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। इस प्रकार आर्थिक विषमता पैदा होती है, प्रति व्यक्ति आय का आँकड़ा ऊपर बढ़ता है लेकिन आम जनता की आय घटती जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी के संस्थान खुलते हैं लेकिन अस्पतालों में प्राथमिक उपचारों को स्थिति भी बेकार हो जाती है।

भारत और वैश्वीकरण :– भारत की अर्थव्यवस्था शुरू से ही मिश्रित स्वभाव की रही है। एक ओर जहा टाटा, अम्बानी हिन्दुजा, बिडला, डालमिया, सहारा जैसी निजी औद्योगिक घराने फूले–फले तो दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ भी उनसे पीछे न रही लेकिन 1990–91 से अब नरसिंह राव की सरकार सत्ता में आयी तो उसने व्यापक रूप से और निजीकरण की नीति शुरू की आज देढ़ दशक पूरा होने के बाद जबकि स्वदेशी को देने वाली सरकार सत्ताहीन है फिर भी उदारीकरण की नीति अपनी–अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है आज भारत पूरी तरह से वैश्वीकरण के साथ जुड़ा गया है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन के एक समझौते के अनुसार भारत को वर्ष 2003 तक आयत पर से प्रतिबन्ध हटाये थे परन्तु भारत में वैश्वीकरण के प्रति रतनी उत्कंठा है कि 2001 में ही सारा मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाना पड़ा। यह ठीक है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के चलते भारत को कुछ आर्थिक लाभ मिलता है लेकिन भारत ने इस सम्बन्ध में जो मुगालते पाल रखे थे कि देखते–ही–देखते इस नीति से भारत का कायाकल्प हो जाएगा वैसा नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप आधारित संरचना के क्षेत्र में कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी निवेश के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में एक अमरीकी कम्पनी के निवेश से डामोल पावर प्रोजेक्ट लगा था परन्तु उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय और भविष्य भारत के लिए अहितकर है क्योंकि भारत की स्वदेशी बिजली उत्पादक कम्पनियों की बिजली से तीन रूपये प्रति यूनिट मिल जाती है लेकिन एनरान पावर कम्पनी की बिजली 10–12 रूपये प्रति यूनिट महाराष्ट्र सरकार खरीदने को विवश है। इस पर भी कम्पनी नित–प्रतिदिन तरह–तरह की धमकियां देती रहती हैं।

आर्थिक उदारीकरण एवं भू–मण्डलीयकरण की नीति अपनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था जो नियमों प्रतिबन्धों एवं लाइसेन्स राज की जटिलता से ग्रस्त थी अब बहुत हद तक खुलकर सांस लेने लगी है। भू–मण्डलीयकरण और आर्थिक उदारीकरण का देश की अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा वही कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों पर वांछित प्रभाव नहीं पड़ा। भू–मण्डलीयकरण की नीति अपनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ गयी तथा भारत सार्वभौम ग्राम की संस्कृति से सम्बद्ध हुआ परन्तु इस नीति के कतिपय कुप्रभाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकते है। जिससे हमें सजग रहना होगा।

1. भूमण्डलीकरण की नीतियां विश्व के विकसित देशों के लिए अधिक हितकारी समझी जाती है। विश्व के विकसित देश भूमण्डलीकरण की परिभाषा के तीन अंगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वे निर्बाध व्यापार प्रवाह, बेरोक–टोक पूंजी और निर्बाध प्रौद्योगिकी प्रवाह की ही आकांक्षा रखते हैं।
2. विश्व के विकसित देश भूमण्डलीकरण की परिभाषा के चौथे अंग–निर्बाध श्रम प्रवाह की पूर्णतया उपेक्षा करते है जबकि श्रम के निर्बाध प्रवाह से जनसंख्या की अधिकता एवं व्याप्त बेरोजगारी से ग्रस्त विकासशील देशों को अधिक लाभ है। विकसित देश विकासशील देशों के अप्रशिक्षित व अकुशल श्रमिकों

को यहाँ नहीं बुलाना चाहते।

3. विकसित देश चाहते हैं कि विकासशील देश व्यापार के सारे प्रतिबन्धों को हटा दें ताकि उनके यहां निर्मित माल इन देशों में निर्बाध गति से प्रवाहित हो।
4. विकसित देश चाहते हैं कि उनकी प्रौद्योगिकी, उनका तकनीकी ज्ञान तथा उनकी पूंजी का प्रवाह विकासशील देशों की ओर निर्बाध रूप से होता रहे ताकि वे अल्पविकसित देशों के कच्चे माल का बहुराष्ट्रीय नियमों के माध्यम से विदोहन कर सकें तथा वहां उपलब्ध सस्ते श्रम का शोषण कर सके।

इतिहास स्वंय को दोहराता लग रहा है। इसके पूर्व भी साम्राज्यवादी देश पूंजी एवं उन्नत प्रौद्योगिकी ज्ञान के प्रवाहों से अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करते थे। वैश्वीकरण की यह अवधारणा पुराने साम्राज्यवादी शोषण का अभिनव संस्करण सा प्रतीत होती है।

5. भूमण्डलीकरण के समर्थकों का तर्क है कि भूमण्डलीकरण की नीतियों को अपनाकर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक बनेगी और वे अधिक तेजी से अपना विकास कर सकेंगे।

भारत ने वर्ष 1991 में घोषित नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाकर व्यापार प्रतिबन्धों को पूरी तरह हटा लिया है तथा आयात शुल्कों में निरन्तर कमी की है, परन्तु उसके निर्यात व्यापार में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, जबकि आयात अधिक बढ़ गये। आज भी विश्व निर्यात व्यापार में भारत का हिस्सा 1.1 प्रतिशत के स्तर तक ही पहुंच सका है।

6. विकसित देश किसी–न–किसी बहाने विकासशील देशों के निर्यात वस्तुओं पर संरक्षणात्मक प्रतिबन्ध लगाकर अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते रहते हैं। उदाहरण के लिये, जब भारत स्कर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय होने लगी और भारत से उसका निर्यात बढ़ने लगा तब अमेरिका में यह भ्रम फैलाकर उनकी मांग को हतोत्साहित किया जाने लगा कि ये स्कर्ट ज्वलनशील पदार्थों से बने हैं। इस तरह अमेरिका में भारतीय स्कर्ट के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया परन्तु यह प्रचार मिथ्या था और जांच पर खरा नहीं उतरा। फलस्वरूप अमेरिका को हमारे निर्यातों पर से प्रतिबन्ध हटाना पड़ा।

इसी तरह यूरोपीय संघ के देशों ने भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर डम्पिंगरोधी शुल्क लगा दिया जिससे इन देशों में भारतीय वस्त्रों की कीमत बढ़ गई।

7. भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण की नीति अपनाने के पश्चात् यह उम्मीद की गयी थी कि इससे कृषि निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की आय एवं रोजगार में वृद्धि होगी, परन्तु विश्व के कृषि व्यापार में भारत का अंश एक प्रतिशत से भी कम है। इस तरह भूमण्डलीकरण के काल में देश में कृषि क्षेत्र उपेक्षित रहा तथा इसके विकास की गति धीमी एवं उतार–चढ़ावों से भरी रही।

निष्कर्ष

इस तरह भूमण्डलीकरण से विकसित देश अधिक लाभान्वित हुए हैं, जबकि विकासशील देश बहुत कम। अतः भारत को चाहिये कि वह चयनात्मक एवं विशिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में ही भूमण्डलीकरण की नीति को अपनाये तथा इस नीति को अंगीकार करते समय देश के उद्योगों विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों से जनता के कल्याण एवं हितों का समुचित ध्यान रखें।

सन्दर्भ ग्रन्थू सची

1. पर्यावरणीय अध्ययन, ए०बी० सक्सेना।
2. पर्यावरणीय मनोविज्ञान, डॉ० रामपाल सिंह, प्रो० अशोक सेवानी एवं डॉ० वी०पी० अग्रवाल।
3. पर्यावरण शिक्षा, डॉ० राधा वल्लभ उपाध्यक्ष।
4. पर्यावरण शिक्षण, जै श्री।
5. Aggarwal, Sukriti and Rout, K.S. (2006): "Environmental academic achievement and Environmental attiude of studens at high school level" EDUTRACK sept. Vol.-6, No.-1, pp 25-28.
6. Alexander, R., Rose, J. and Woodhead, C. (1992): "Curriculum organisation and classroom practice in Primary Schools: A Discussion Paper", London, Department of Education and Science.
7. Best, J.W. (2004): "Research in Education" prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, p.146.